any time limit for getting the report. This is No. 1. Secondly, I would like to know the details of facilities being provided in the CGHS dispensaries. Lastly, Sir, opening of a new CGHS unit means it would require creation of posts. And, this can be done only after the recommendations, for this purpose, have been made by the SIU. Since the report of the SIU has not been received and there is no time limit for getting the report of the SIU, how are you going to create new posts.' First of all. is there any need to open new CGHS dispensaries'? And, if there is a need to open new dispensaries, this would, definitely require creation of new posts.

DR. C. P. THAKUR : The SIU has recommended norms for allopathic dispensaries, but this has been challenged in the Court by the Gr. III and Gr, IV employees. Because of this, it is slightly delayed. And, what we have done is, we have requested the Solicitor-General to appoint some senior advocate for arguing the case so (hat the matter could be expedited. Then, in the matter of extending ayurveda and homoeopathy systems of medicines, the work has just started: I have also requested them to finalise the recommendations soon so that we can take up the opening of new dispensaries in different parts of the country.

National Press Centre

*564. SHRI K. RAMA MOHANA RAO : Will the Minister of INFORMA-TION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that setting up of National Press Centre is hanging fire since Eighth Five Year Plan;

(b) if so, the reasons for not taking up the project since then; and

(c) the original estimate for this project and the revised estimate?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRJMATI SUSHMA SWARAJ) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The scheme 'Setting up of National Press Centre at New Delhi' had been included in Eighth Five Year Plan and continued in the Ninth Plan of PIB. The project could not be taken up as the possession of encumbrance free plot of land was not given by Ministry of Urban Development. In the absence of possession of the land, no detailed estimate could be prepared. However, based onrough'estimate, an outlay of Rs. 20.50 crores was made in the Ninth Five Year Plan.

An alternative plot measuring 1.955 acres has now been allotted at Raisina Road. New Delhi. A tentative outlay of Rs. 35 crores has been proposed for this project during the Tenth Plan Period and a provision of Rs. 9 crores has been made in the Annual Plan for financial year 2002-2003.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir. the idea behind selling up the National Press Centre is to have a world-class media centre to keep pace with the fast and rapid information that is being disseminated to the society by the print "and electronic media. The Centre proposes to have state-of-the-art paraphernalia such as Press lounge, conference station, briefing room, digital library and other most modern and advanced equipments. Since the existing Press Centre housed in Shastri Bhawan is not able to provide professional facilities to the presspersons, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that about two acres of land, which was acquired last year, has still not been physically handed over to the Press Information Bureau. If 'yes', I would like to know the reasons for the delay in handing over the land physically to the PIB. The land should be handed over to'them soon so that the PIB can start the construction work.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी , यह ठीक है कि लैंड का फिजिकल पजेशन अभी तक हमें नहीं मिला है । लेकिन उसका एक कारण है कि वहां पर हमारे एमओएम राज्य मंत्री श्रीपद नाइक उसमें रह रहें हैं और उन्हें दूसरा एक बंगला अलाट हो गया है । उस बंगले में रिनोवेशन चल रहे हैं और उन्हें दूसरा एक बंगला अलाट हो गया है । उस बंगले में रिनोवेशन चल रहा है । जैसे ही रिनोवेशन पूरा हो जाएगा वे वहां शिफट कर जाएंगें और उसका फिजिकल पजेशन हमे मिल जाएगा । लेकिन फिजिकल पजेशन में किसी तरह की देरी नहीं है क्योंकि साथ साथ हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे है । साइमलटेनियसली प्लानिंग का काम चल रहा है जिसके लिए फिजिकल पजेशन की आवश्यकता नहीं है । लेकिन जैसे मैंने लिखित जवाब में भी बताया कि माननीय सांसदों की ये जिज्ञासाएं बहुत वैध इसलिए बन जाती है कि 1994 में जो जमीन का टुकड़ा दिया गया था 2002 तक कोई सेंटर का काम उसमें नहीं चला । इसलिए उनको लगता है कि कहीं आगे तो देरी नहीं होगी । लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहतीहूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो चीज आई और दसवीं पंचवर्षीय योजना तक जो नहीं बनी- यहां शहरी विकास मंत्री जी श्री अनन्त कुमार जी बैठे है , मैं उनको हदय से बधाई देना चाहती हूं कि बहुत ही जल्दी उन्होनें हमको जमीन का टुकड़ा अलाट कर दिया है , उस पर भी भूमि पूजन 5 दिसम्बर को हो गया था प्लानिंग का काम चल रहा है । फिजिकल पजेशन पर अभी तक नहीं भी मिला तो वह डिले का कारण नहीं बनेगा । इसके कारण कंस्ट्रक्शन में डिले बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अगर फिजिकल पजेशन मिल जाता है तो भी इस समय हम प्लानिंग की स्टेज पर ही होते हैं । वह प्लानिंग का काम चल रहा है और मानीय प्रधान मंत्री जी ने उस दिन

भूमि पूजन के समय , समारोह में बोलते हुए हमसे कहा था कि बहुत जल्दी इसको बनाकर भी तैयार करना है । तो मै "सदन" को आश्वस्त करना चाहती हूं कि बहुत जल्दी यह स्टेट आफ द आर्ट इक्विपमेंट लिए हुए मीडिया सेंटर तैयार होगा । सभापति जी , यह बात सही है कि गीता कृष्णन कमेटी रिपोर्ट ने अपनी अनुशंसा में यह कहा था कि केवल राज्यों की राजधानियों में पीआईबी के कार्यालय रखें जाएं और बाकी सारे कार्यालय हटा दिए जाएं । ऐसे 16 कार्यालय थे जो राज्यों की राजधानियों के अलावा थे । लेकिन हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज करके पूरी समीक्षा करने के बाद तय किया है कि उसमें से केवल 5 कार्यालय हम बंद करेगें, बाकी 11 कार्यालय हम बंद नहीं करेगें । अब चूंकि गीता कृष्णन कमेटी खर्चा भी घटाना चाहती थीं , बाकी चीजों को भी देखना चाहती थीं , इसलिए हमने उनकी सारीअनुश्संसाएं मानी नहीं हैं ।उन्होनें तो हम से 7500 में से 5700 पोस्टें लेने की बात कर दी थी , कुल रकमेंडशन में भी हमने 1334 पोस्टें सरंडर करना माना है और यह जो 16 पीआईबी आफिसेज थे, जो राज्यों की राजधानियों के अलावा थे , उनमें से 11 हम बरकरार रखेंगें और केवल 5 कार्यालय हमने बंद करने का फैसला किया है ।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that the Geetha Krishnan Committee recommended the abolition of PIB branehes which are not located at the State headquarters. If yes, does it not hamper the newspapers, especially, the regional language publications; If it is true, how is the Ministry looking into the issue and what steps is the Ministry taking for retaining the existing PIB offices in the country?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी , पहले मैं यह बता दूं कि इसमें पीआईबी की अपनी कोई गलती नहीं है ओर न वहां का कोई ब्यूरोक्रेटिक टैंगल इसके अंदर था जिसके कारण हमें जमीन नहीं मिली । यह जमीन फार्म इनकंब्रेंस नही थी और इसीलिए हम लोग बार-बार यहां तक कि मेरे अपने स्तर पर , हम लोग अर्बन डिवलपर्मेट मिनिस्टर से मिटिंगं लेते हैं रहें और वहां भी उनकी कोई ब्यूरोक्रेटिक गलती नही थी ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I do not know whether there will be lime left for the reply.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I will give a very short reply, provided you ask a very short question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am really sorry to point out that this is a typical bureaucratic reply—I am not blaming the hon. Minister—because I had a small role to play in this. I was the Deputy Chairman of the Planning Commission at that point of time when the scheme was approved, and a case was made out by the Department as if the Yamuna would be set on fire if

this case was not approved and included in the'Eighth Plan itself. The whole. 8th Plan went; the whole 9th Plan went. In the 10th Plan now, Rs. 30 crores have been allocated. My simple question is this. PIB is also a Government outfit; it is not outside the Government. How is it that it took ten years' to identify.a piece of land and to hand over that piece of land for construction? Now, can the hon. Minister give any specific time-frame within which this project would be completed?

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रणव दा, अगर आप मेरा पूरा जवाब सुन लेते तो शायद आप स्वंय यह मान लेते कि उनकी गलती नहीं थी , क्योंकि जो जमीन का टुकड़ा था उस जमीन के टुकड़े में उस बंगले में, दो सांसदों की जमीन आती थीं और दो सांसद उस कोठी में रह रहे थे। इसलिए बार-बार उनसे यह प्रार्थना की जाती थी कि या तो हम उन्हें दूसरी कोठियां दे देते, वें वहां शिफट कर जाए ताकि यह जमीन दे दी जाए, लेकिन मैं आप से अब यह कह रही हूं कि अब हमको क्योंकि एक ऐसी जमीन दे दी गई है जिसको हमें फिजिकल पोजैशन देने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम फ्रेम में एक तारीख तो नहीं दे पारही हूं लेकिन मैं आपके कह रही हूं कि बहुत जल्दी मीडिया सैन्टर को बना कर हम साकार स्वरूप दे देगें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is why it took eight years. From 1994 to 2002. in eight years, you could not resolve the problem and get an encumbrance-free piece of land! *(Interruptions)...*

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, the Press is very important. It is the Fourth Estate. May I know from the hon. Minister whether this National Press Centre—when it is completed—will function as an extension of the Ministry; or, are you going to get involved people from the Press, the journalists and others, who know what needs to be done in this modern age?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी , मंत्रालय का कार्यालय है , इसलिए काम तो मंत्रालय के अधीन ही करेगा, लेकिन जर्नलिस्ट्स के लिए होगा, फैसिलिटिज सारी जो दी जायेगीं वे पत्रकारों के लिए होगीं। लेकिन मंत्रालय का कार्यालय तो मंत्रालय के अधीन ही चलेगा।

Water shortage in South Delhi

*565. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of water in several areas in South Delhi during the last few months;